DPDP अधिनियम: कंसेंट मैनेजर रजिस्ट्रेशन ढाँचा लॉन्च, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की वेबसाइट शुरू



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023** के तहत **कंसेंट मैनेजरों का पंजीकरण-ढाँचा** शुरू कर दिया है - यह 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ। MeitY सचिव **एस. कृष्णन** ने ऑनलाइन पोर्टल **dpbi.gov.in** (Data Protection Board of India पोर्टल) लॉन्च किया, जिससे योग्य कंपनियाँ कंसेंट मैनेजर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगी।

कंसेंट मैनेजर कौन है

कंसेंट मैनेजर वह पंजीकृत इकाई है जो **डेटा प्रिंसिपल** (जिस व्यक्ति का डेटा है) को अपनी सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने की सुविधा एक सुलभ, पारदर्शी और इंटरऑपरेबल (परस्पर-संचालनीय) प्लेटफॉर्म पर देती है। कंसेंट मैनेजर डेटा प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी होते हैं - यानी ये उपयोगकर्ता के 'सहमति-प्रबंधक' हैं, कंपनियों के एजेंट नहीं।

पंजीकरण की शर्तें और प्रक्रिया

- **पात्रता:** भारत में निगमित (incorporated) कंपनियाँ, जिनके पास पर्याप्त तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता हो; **न्यूनतम नेट वर्थ 2 करोड़ रुपये** अनिवार्य।
- **प्रक्रिया:** पात्र कंपनियाँ dpbi.gov.in पोर्टल से डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) के पास आवेदन करेंगी; बोर्ड आवश्यकताओं के आधार पर मूल्यांकन कर पंजीकरण देगा; पंजीकृत कंसेंट मैनेजरों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी।
- **आगामी चरण:** डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों, डेटा फिड्यूशरी के दायित्वों और बोर्ड की जाँच-दंड प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रमुख प्रावधान **13 मई 2027** से प्रभावी होंगे।

पृष्ठभूमि: DPDP अधिनियम

DPDP अधिनियम, 2023 भारत का प्रमुख व्यक्तिगत डेटा-संरक्षण कानून है, जो डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की संरचना देता है। कंसेंट मैनेजर ढाँचा इस कानून के चरणबद्ध क्रियान्वयन का पहला बड़ा ऑपरेशनल कदम है - इससे 'सहमति-आधारित डेटा अर्थव्यवस्था' की संस्थागत नींव पड़ती है।

> **संबंधित लेख:** DPDP अधिनियम और प्रेस की स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. DPDP अधिनियम के तहत कंसेंट मैनेजर पंजीकरण-ढाँचे (नवंबर 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ढाँचा 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ

2. आवेदन के लिए dpbi.gov.in पोर्टल लॉन्च हुआ

3. पंजीकरण हेतु न्यूनतम नेट वर्थ 20 करोड़ रुपये चाहिए

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▶ उत्तर और व्याख्या

प्रश्न 2. DPDP अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान (डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, दंड-प्रक्रिया आदि) कब से प्रभावी होंगे?

(a) 1 जनवरी 2027

(b) 13 मई 2027

(c) 15 अगस्त 2027

(d) 1 अप्रैल 2028

▶ उत्तर और व्याख्या

मेन्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

कंसेंट मैनेजर ढाँचा भारत की सहमति-आधारित डेटा अर्थव्यवस्था की संस्थागत नींव है। DPDP अधिनियम के चरणबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा कीजिए और आगे की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए - 15 अंक)

उत्तर की रूपरेखा:

भूमिका में: DPDP अधिनियम, 2023 और 13 नवंबर 2026 से कंसेंट मैनेजर पंजीकरण-ढाँचे की शुरुआत।

PCSMANTRA.COM